भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

19.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3175 का उत्तर

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजनाएं

3175. श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोगीघोपा से बारपेटा और हाजो के रास्ते अमीनगांव तक पहले से अस्तित्व वाली रेललाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के आरंभ होने की कोई तारीख प्रस्तावित है;

(ग) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रेललाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): बारपेटा, सरथेबारी होते हुए जोगीघोपा-गुवाहाटी नई लाइन (136 कि.मी.) के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालयों इत्यादि सहित विभिन्न स्तरों पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के लिए

औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/शिकायतें/सुझाव प्राप्त होना एक सतत और चलायमान प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। हालाँकि, इनकी जाँच की जाती है और व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25) के दौरान असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 2,499 किलोमीटर कुल लंबाई के 21 सर्वेक्षण (17 नई लाइन एवं 04 दोहरीकरण) स्वीकृत कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 1,368 किलोमीटर कुल लंबाई की 74,972 करोड़ रु. लागत की 18 रेल परियोजनाएं (13 नई लाइनें और 05 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 40,549 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

कार्यों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी. में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	13	896	81	34,616
दोहरीकरण	5	472	232	5,933
कुल	18	1,368	313	40,549

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

असम राज्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना संबधी परियोजनाओं और अन्य कार्यों हेतु औसत बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,122 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	10,376 करोड़ रु. (लगभग 5 गुना)

असम राज्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेल पथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	333 किलोमीटर	66.6 कि.मी./वर्ष
2014-24	1,728 किलोमीटर	172.8 कि.मी./वर्ष (लगभग 3 गुना)

किसी भी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा साझा लागत के भाग को जमा कराना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति आदि के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना, (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iv) क्षेत्रीय

स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लीयरेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(घ) भारतीय रेल के आकार, भौगोलिक वितरण और परिचालनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और इन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रिकीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रेलों द्वारा भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेज कर नियमित आधार पर भरा जाता है।

कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान दो बड़ी परीक्षाओं जिनमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	केन्द्र	दिवस	पालियां
एल2 - एल6	1.26 करोड़	211	726	68	133
एल1	1.1 करोड़	191	551	33	99

इन परीक्षाओं के आधार पर, रेलों में 130581 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों और संसाधनों को जुटाने तथा जनशक्ति को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। रेलवे ने इन सभी

चुनौतियों को पार किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-2014 तक की तुलना में वर्ष 2014-2025 से 2023-2024 तक के दौरान रेलों पर की गई भर्तियां निम्नानुसार हैं-

अवधि	भर्तियां*
2004-2005 से 2013-2014 तक	4.11 लाख
2014-2025 से 2023-2024 तक	5.02 लाख

*लेवल-1 और सुरक्षा संबंधी पदों सहित

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;
- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।

तदनुसार, सहायक लोको पायलटों, तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कोटियों और लेवल-1

के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई हैं।

दिनांक 25.11.2024 से 30.12.2024 तक चार अधिसूचनाओं के लिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी) आयोजित की गई हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	केन्द्र	दिवस	पालियां
एएलपी के पद हेतु प्रथम चरण सीबीटी (18,799 रिक्तियां)	1840347	156	346	5	15
रे.सु.ब.-उप निरीक्षक के पद के लिए सीबीटी (452 रिक्तियां)	1535635	143	306	5	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी (7,951 रिक्तियां)	1101266	146	323	3	9
तकनीशियन पद के लिए सीबीटी (14,298 रिक्तियां)	2699892	139	312	9	27

इसके अलावा, कांस्टेबल के पद के लिए आरपीएफ सीईएन संख्या 02/2024 (4208 रिक्तियां) के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 02.03.2025 से शुरू हो गई है। सहायक लोको पायलट के पद के लिए सीईएन संख्या 01/2024 के लिए द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-II) दिनांक 19.03.2025 और 20.03.2025 को निर्धारित है।

****